June **15, 2023**

Assam CABINET

2

KEY DECISIONS

Discontinuation of Physical Non-judicial Stamps

Physical non-judicial stamps to be discontinued and digital stamping to be expanded with notification of necessary rules governing digital stamping

- **Key Points**
  - Sale of physical non-judicial stamps from treasuries to be discontinued with effect from **1 July 2023**
  - Physical stamps purchased before **30 June 2023** by vendors and common people for legitimate transactions to be allowed till **30 September 2023**
  - Non-judicial physical stamps to be discontinued with effect from **1 October 2023**, except in special unforeseen cases. In such cases, use of physical stamps may be allowed by District Registrar with prior permission from Superintendent of Stamps
  - Rules governing digital stamping – Assam Digital Stamp (Payment of Duty by means of e-Stamping) Rules, 2023 – to be notified

Existing stamp vendors with valid licences will be rehabilitated by converting their establishments into Citizen Service Centres, for which ₹1 lakh will be provided

- The decision to give a boost to digital stamping and ensure the State Government cuts down on costs by providing a faster and more transparent payment process via 100% Digital Stamping

Scanned by TapScanner

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने ज्वलनशील मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

खबर संवाददाता

तिनसुकिया, 8 मई। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा फिर से एक ज्वलनशील मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनएचआरसीसीबी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत थर्ड द्वारा अत्यधिक कीमतों पर स्टाम्प पेपरों की बेईमानी से बिक्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को लेकर राज्य सरकार से संपर्क साधा। हमारे संवाददाता को बताते हुए उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में आया है कि पंजीकृत विक्रेता प्राय: स्टाम्प पेपर शीघ्र उपलब्ध कराने में असमर्थ रहते हैं, जबकि बाहरी लोग इस स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें अधिक दामों पर बेच रहे हैं। असम के एक जिम्मेदार नागरिक और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के प्रतिनिधि के रूप में, मैंने इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। स्टाम्प पेपर आवश्यक कानूनी दस्तावेज हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि संपत्ति लेनदेन, समझौते और शपथ पत्र। वे इन लेन-देन की वैधता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, पंजीकृत विक्रेताओं से स्टांप पेपर की अनुपलब्धता और बाद में कीमतों में वृद्धि से असम के नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल कानूनी प्रणाली में लोगों के विश्वास को कम करती है बल्कि भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाती है। इस संबंध में ब्यूरो के मीडिया अधिकारी आशीष अग्रवाल ने कहा राज्य सरकार को निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना चाहिए। क्रमशः पंजीकृत विक्रेताओं से स्टांप पेपरों की अनुपलब्धता और बाद में अपंजीकृत विक्रेताओं के अत्यधिक मूल्य वसूलने की तत्काल जांच करें। स्टांप पेपर विक्रेताओं के लिए सख्त लाइसेंसिंग और निगरानी तंत्र लागू करके नियामक ढांचे को मजबूत करे। जमाखोरी, कालाबाजारी या स्टाम्प पेपरों की बिक्री से अवैध रूप से मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। पंजीकृत विक्रेताओं को स्टाम्प पेपर की सुचारू और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित हितधारकों, जैसे राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और रजिस्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करें। एक हेल्पलाइन या ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करें जहां नागरिक स्टाम्प पेपर की अनुपलब्धता या अनुचित मूल्य निर्धारण की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी शिकायतों को सुना जाता है और तुरंत संबोधित किया जाता है। यह जानकारी हमें ब्युरो के जिला मीडिया अधिकारी आशीष अग्रवाल द्वारा प्राप्त हुई।

हीरालाल शर्मा...

Scanned by TapScanner

The Assam Tribune
PUBLISHED SIMULTANEOUSLY FROM GUWAHATI & DIBRUGARH

Plea to stop sale of stamp papers at higher prices

A CORRESPONDENT

JAMUGURIHAT, May 9: The people in Assam face difficulties in obtaining government stamp papers required for works like land registration, conclusion of various agreements and court functions. A large sum of money has to be paid against the fixed price to purchase the papers. One has to pay Rs 150 to Rs 170 to buy a stamp paper worth Rs 100. The conscious citizens feel that it has become necessary to stop the current practice of selling the government stamp papers at higher prices once and for all in the State.

The National Human Rights and Crime Control Bureau of Assam considers this issue to be very sensitive. Nishant Thard, State president of the organisation, said in a press statement through the state media officer Mrinmay Kumar Nath that the NHRCCB, Assam, has written to the Chief Minister and the Revenue Minister to make the stamp papers available to everyone. The organisation has requested the authority concerned to take necessary action in this regard. The State president also requested the government to take necessary measures to ensure easy access to online stamp papers in Assam.

Scanned by TapScanner